

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 03/2018

(Rcms no. 2018/00004)

उनवानी प्रकरण :-

1. अशोक पुत्र महावीर जाति ब्राहमण निवासी बौरैली तहसील बसेडी जिला धौलपुर ————— अपीलान्त।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ——— रेस्पोजेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 6.9.2017

तहसीलदार बसेडी प्र. सं. 20/2017

उनवानी राज0 सरकार बनाम अशोक

अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से :- श्री दिलीप शर्मा अभिभाषक।
2. रेस्पोजेण्ट की ओर से :- पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :-28.05.2018

निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 6.9.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का बौरैली ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नम्बर 769, 764, 782, 753 रकवा 01.97 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ताल पर फसल खरीफ सम्बत् 2074 में अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के खिलाफ नोटिस जारी किये व अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलान्त द्वारा गैर मुमकिन ताल की जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलान्त की स्वयं की खातेदारी की जमीन है। पैमाइश की जाकर स्वयं मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में देख सकते हैं। अपीलान्त को अनुपस्थित दिखाकर पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये जाकर लगान का 50 गुना शास्ती 1281/—रूपये अधिरोपित की जाकर आदेश दिनांक 6.9.2017 पारित किया गया है। आदेश खिलाफ कायदा कानून व रूवेदार मिसिल होने से लायक खारिजी के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के कब्जे का जो आधार माना है वह गलत व अपर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये गये हैं उक्त प्रकरण में अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है इस प्रकार निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो अतिक्रमण बताया है वह अपीलान्त की खातेदारी की आराजी में है। फिर भी यदि मौके पर नाप कराई जावे व अपीलान्त का अतिक्रमण निकलता है तो वह छोड़ने को तैयार है। रिपोर्ट



जिला कलक्टर
धौलपुर

पटवारी हल्का द्वारा मौके व वास्तविकता के विपरीत की गई है अपीलान्त का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है इस बावत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। उक्त फैसले की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 15.11.2017 को हुई। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.9.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 6.9.2017 नकल फोटो प्रति आदेश दिनांक 21.12.2017 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील फोटो प्रति एफ.आई.आर पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्त को पश्चात्वती अतिक्रमी मानते हुए भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के तहत अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं जो खिलाफ कानून एवं न्याय संगत नहीं है। धारा 91(6) की कार्यवाही करने से पूर्व तहसीलदार को जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति लेनी होती है। बिना पूर्व अनुमति लिये तहसीलदार 91(6) की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 6.9.2017 को 91(6) की कार्यवाही के आदेश दिये तथ दिनांक 6.10.2017 को धारा 91(2) के तहत कार्यवाही के आदेश दिये हैं इस प्रकार दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 369/2017 की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपीलान्त के विरुद्ध बलपूर्वक/प्रतिरोधी कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्देश दिये हैं। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलान्त द्वारा गैर मुमकिन ताल की जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलान्त की स्वयं की खातेदारी की जमीन है। पैमाइश की जाकर स्वयं मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में देख सकते हैं। अपीलान्त को अनुपस्थित दिखाकर पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये जाकर लगान का 50 गुना शास्ती 1281/-रूपये अधिरोपित की जाकर आदेश दिनांक 6.9.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये गये हैं उक्त प्रकरण में अपीलान्त को न तो पटवारी हल्का से जिरह करने और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्त को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई है अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.8.2017, 8.8.2017 26.8.2017 एवं निर्णय दिनांक 6.9.2017 को स्वयं उपस्थित था जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट से होती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक से पूर्व एवं निर्णय दिनांक को स्वयं उपस्थित था उसको यदि पटवारी से जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय की माँग करनी चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट ने जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की माँग की हो तथा अधीनस्थ न्यायालय ने समय नहीं दिया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.9.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:-

1. यह तथ्य सही कि है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई है क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.8.2017, 8.8.2017 26.8.2017 एवं निर्णय दिनांक 6.9.2017 को स्वयं उपस्थित था जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट से होती है।
- 3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक से पूर्व एवं निर्णय दिनांक को स्वयं उपस्थित था उसको यदि पटवारी से जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय की माँग करनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट ने जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की माँग की हो तथा अधीनस्थ न्यायालय ने समय नहीं दिया हो।
- 4- पटवारी हल्का के बयान प्रफोर्मा पर लिये गये हैं जो न्याय संगत नहीं हैं। जो प्रभावहीन हो जाते हैं।
- 5- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय में पैरा नम्बर 2 में अकिंत किया है कि अप्रार्थीयान स्वयं उपस्थित आये तथा अतिक्रमण स्वीकार



/अस्वीकार किया। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अतिक्रमण स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार किया है। पैरा नम्बर 3 में अंकित है कि अप्रार्थीयान नोटिस की नियमानुसार तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। जबकि आर्डरशीट पर हो रहे अपीलान्त के उपस्थित के हस्ताक्षर से विदित है कि अपीलान्त उपस्थित था। इस प्रकार निर्णय में विरोधाभास है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया गया है जो स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है।

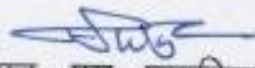
- 6- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है उस पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपीलान्त के विरुद्ध बलपूर्वक/प्रतिरोधी कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्देश दिये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 6.9.2017 त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाना एवं अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.9.2017 अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार बसेंजी को प्रति प्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फँसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(एन. एम. पहाडिया)
जिल्हा न्यायालय, धुळे, महाराष्ट्र
धुळे